

आरत के राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाराण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 1969/वैशाख 11, 1891

No. 169] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 1969/VAISAKHA II, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May 1969

S.O. 1733.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas since the commencement of the Constitution, Advance Tax collections made under the Income-tax Act have been taken into account in determining the net proceeds of taxes on income for purposes of article 270(2) of the Constitution only on completion of regular assessment;

And whereas successive Finance Commissions have recommended the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes on income under article 280(3)(a) of the Constitution on the said basis;

And whereas the Comptroller and Auditor-General of India has also certified the net proceeds of taxes on income under article 279(1) of the Constitution in each of the financial years until and including 1966-67 on the said basis;

And whereas it is now considered that the Advance Tax collections made in a financial year should be taken into account in determining the net proceeds of taxes on income in that year and not be left over for such determination in subsequent years on completion of regular assessment as hitherto;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (a) and (c) of clause (3) of article 280 of the Constitution of India, the President is pleased to refer the following further matters to the Finance Commission, constituted by S.O. No. 812, dated the 29th February, 1968, namely:—

- (a) the distribution of the Advance Tax already collected and not included in the net proceeds of taxes on income in the financial years until and including 1966-67 as certified by the Comptroller and Auditor-General of India;
- (b) the changes, if any, in the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes on income as prescribed in the Constitution (Distribution of Revenue) Order, 1965, in so far as the taxes on income collected in the financial years 1967-68 and 1968-69 are concerned, in the event of the net proceeds thereof being certified by the Comptroller and Auditor-General of India after taking into account the Advance Tax collected in the respective years; and
- (c) the distribution of the net proceeds of taxes on income in each of the financial years 1969-70 to 1973-74 as determined on the revised basis,

2. The Commission shall take into account the effect of the recommendations made by them on the matters specified in paragraph 1 above in making their recommendations, under S.O. 812 aforesaid, as to the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds under sub-clause (a) of clause (3) of article 280 of the Constitution and also as to the determination of the sums to be paid as grants-in-aid of the revenues of the States in need of assistance under clause (1) of article 275 of the Constitution.

ZAKIR HUSAIN,

President.

[No. 13(5)-B/69.]

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(ग्राम्य विभाग)

ग्राम्य सूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1969

कांग आ० 1734.—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है:—

आदेश

जब कि संविधान के लागू होने से लेकर, संविधान के अनुच्छेद 270(2) के प्रयोजनों के लिए, आय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियां आकर्ते समय, केवल नियमित रूप से कर-निर्धारण हो जाने के बावजूद, आपकर अधिनियम के अधीन करों की पेशागी व्यापारी की रकमों को हिसाब में लिया जाता रहा है।

और जब कि एक के बाद एक सभी वित्त आयोगों ने संविधान के अनुच्छेद 280(3)(क) के अधीन आय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियों को संबंधी और राज्यों के बीच वितरण के लिए उक्त आधार की सिफारिश की है;

और जब कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अधीन 1966-67 तक और उस वर्ष सहित, प्रत्येक वित्त-वर्ष के आय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियों की रकमे उक्त आधार पर प्रमाणित कर दी हैं;

श्रीर जब कि अब महसूस किया जाता है कि किसी वित्त-वर्ष में की गयी पेशागी वसूली की रकमें उस वर्ष आय संबंधी कर की शुद्ध प्राप्तियाँ आने ते समय हिसाब में ली जानी चाहिए, न कि उन्हें बाद के वर्षों में इस प्रकार आंका जाना चाहिए जैसा कि अब तक होता रहा है;

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा (3) की उपधाराओं (क) श्रीर (ग) के अनुसार, राष्ट्रपति ने 29 फरवरी, 1968 के का० आ० संख्या 812 के अधीन गठित विषयायोग को निम्नलिखित और मामले विचारार्थ सौंपे हैं, अर्थात् :—

- (क) 1966-67 तक और उस वर्ष सहित आय संबंधी करों की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित शुद्ध प्राप्तियों में शामिल न की गयी, पहले से पेशागी वसूल की गयी कर की रकम का वितरण ;
- (ख) जहां तक 1967-68 और 1968-69 के वित्त-वर्षों में आय संबंधी करों की वसूल रकमों का संबंध है, इन वर्षों में पेशागी वसूल किये गये करों की रकमों को हिसाब में लेने के बाद, आय संबंधी करों की वसूल शुद्ध रकमों के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दिये जाने पर, संविधान के (राजस्वों का वितरण) आदेश, 1965 में विहित संघ और राज्यों के बीच आय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण में कोई परिवर्तन ; और
- (ग) 1969-70 से 1973-74 तक के प्रत्येक वित्त-वर्ष में, आय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियों का संशोधित आधार के अनुसार वितरण ;

2. आयोग उपर्युक्त का० आ० 812 के अधीन केन्द्र और राज्यों के बीच आय संबंधी करों की बांटी जाने वाली और बांटी जा सकने वाली शुद्ध प्राप्तियों के वितरण और संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा (3) की उपधारा (क) के अधीन ऐसी प्राप्तियों में से प्रत्येक राज्य के हिस्से के निर्धारण और संविधान के अनुच्छेद 275 की धारा (1) के अधीन उन राज्यों के राजस्व-सहायक अनुदानों के रूप में दी जाने वाली रकमों के निर्धारण के संबंध में, जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो, सिफारिशों करते समय, उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में की गयी अपनी सिफारिशों के प्रभाष का भी व्याप रखेगा ।

जाकिर हुसैन,

राष्ट्रपति ।

[संख्या एफ० 13(5)-बी०/69.]

ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव ।

